bir, these were som_e of th_e impor tant things which I mentioned and I think, I have been abla to answei almost all the questions which were raised by the hon. Members. Sir, there i_s on_e more thing which I forgol to mention that we have aiso decided that all the janata cloth will be transferred to the handloom sector. Already this year—1986-87—500 million metres of janata cloth will be produced by the end *o** the 7th Five Year Plan they will be producing a total of 700 million $metre_s$ of janata cloth. And this has been dona, particularly keeping in view tlie fact that 20 per cent of the $hancdoom_s$ in the rural areas, particularly in the remote villages were idle. And we have suggested to the Stata Governments that these handlooms which were dormant and which were idle should get this janata cloth production so that they are in a position to earn their livelihood for at least six months or eight months in a year.

Sir, with these few words, I would certainly like to say that I have tried to explain everything possible.

AN HON. MEMBER: Regarding the relief scheme.. ,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN); The parliamentary procedure is that after the reply, no further clarifications are allowed to be asked. But I do not know if the hon. Minister i_s willing, he can answer. But the normal procedure is not that.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM; Regarding the credit facility scheme for the employees of the Centra.1 Government, our Chief Minister, Dr. MGR has written a letter to the Home Minister. Will the Government accept the scheme for the employees of Central Government at least in Tamil Nadu?

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: He has written to the Home Minister and only Home Minister can answer it.

| SHRI A. G. KULKARNI: The hon. Minister said about dhotis and sarees and I had given him statistics as to how much of dhotis and sarees are required in this country. ll_e ha_s not elaborated on this point whether what I said was correct or not.

SHRI KHURSHID ALAM KHAN: i My only contention i_s that there is no shortage of dhotis and sarees.

REFERENCE TO THE NEED TO NATIONALISE BENGAL POTTERIES

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Now we take up special mentions. Shri Sukomal Sen.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal); The question of nationalisation of Bengal Potteries of Calcutta has been hanging fire for lh_e last several years leading to total uncertainty to the industry and about five thousand workers employed in it. After the takeover of the unit by the Union Government in 1976, 5-man expert committee- was appointed which opined that adequate working .capital and necessary modernisation of this unit can revive it into a profitable unit. Moreover, the Tata Consultancy Service also in their report expressed the same.opinion. In this background, discussions took place between the Joint Secretary in the Industry Ministry and Bengal Potteries on 23rd May 1986 when the Government assured to send a draft agreement to trade union by 30th May, 1986 laying down basis for nationalisation of the unit. The promised draft has not yet reached the trade union.

Between 1983 and 1985, the Government spent about Rs. 14 crores for payment of salaries to the workers although there wa_s little production in the unit. Only Es. 5 $crore_s$ as working capital and another Rs. 181 crores for other $purpose_s$ can revive the unit into a profitable one. In the circumstances I would request the

[Shri Sukomal Sen]
Government to take steps for immediate nationalisation of Bengal Potteries which once enjoyed being the biggest crockery producing unit in whole ol Asia.

REFERENCE TO THE FLOODS IN VARIOUS STATES

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : सर, देश के अन्दर हाल के दिनों में जो बाढ़ की विभीषिका है, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । बाढ़ से देश के कई राज्य भयंकर रूप से प्रभावित हैं । दो-तीन दिनों से जो वर्षा हुई है, उससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, असम आज खतरनाक ढंग से प्रभावित हैं । कुछ समय पहले गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू एण्ड काश्मीर, मध्य प्रदेश आदि बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित थे । अब रावी नदी में बाढ़ से पंजाब राज्य में गुरदासपुर और अमृतसर जिले काफी प्रभावित हैं । जमुना और गंगा नदियां खतरे के बिन्दु से ऊपर बह रही हैं । सोन नदी खतरे को सीमा पार कर गई है, बिहार को तमाम नदियों में बाढ़ भयंकर रूप से आई हुई है । बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है ।

उत्तर प्रदेश में ही 81 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हजारों गांव जलमग्न हैं, काफी मात्रा में पशुधन और सम्पत्ति की बरबादी हुई है, हजारों मकान ध्वस्त हो गये हैं । बिहार में ही तीन लाख लोग गृहविहीन हो चुके हैं । कई तट बंध सरकारी तन्त्र की लापरवाही और उदासीनता से टूट गये हैं जिससे लोगों की तबाही बढ़ गई है ।

इस बाढ़ के कारण काफी लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है । बाढ़ से हर साल अरबों की क्षति होती है । एक अनुमान के अनुसार हर साल करीब दस अरब की क्षति होती है । 1983 में सब से अधिक क्षति हुई और नुकसान की रकम 22 करोड़ रुपये है ।

बाढ़ उन्मुख क्षेत्र 40 मिलियन हैक्टर है, लेकिन अभी तक सरकार 12 मिलियन हैक्टर में ही बाढ़-नियंत्रण कर पाई है । चिन्ता की बात यह है कि बाढ़ नियन्त्रण पर अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी बाढ़ का हर क्षेत्र हर साल बढ़ता जा रहा है । बाढ़ पर नियंत्रण के लिये सरकार ने जो भी योजना बनाई है, उसके अधिक रुपये करप्शन में चले जाने के कारण बाढ़ की योजनायें बिलकुल ही असफल सी हो चुकी हैं, और यही कारण है कि देश के अन्दर बाढ़ की विभीषिका रोज-ब-रोज बढ़ती चली जा रही है और अधिक से अधिक क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आते चले जा रहे हैं । इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बाढ़ कोई एक साल की बीमारी नहीं है, यह तो हर साल आती है और इससे अधिक नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है । इसलिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि बाढ़ नियन्त्रण के लिये एक अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिये । अभी जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुये हैं उनके लिये सरकार की ओर से कोई खास सहायता की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । इसलिये उन लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है । इसलिये मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह राज्य सरकारों को आदेश दे और केन्द्र से भी काफी सहायता दे ताकि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको सहायता मिल सके और साथ ही में यह भी अपील करना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के लिये एक दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिये ताकि बाढ़ की समस्या पर हमेशा के लिये नियन्त्रण किया जा सके और जिसकी वजह से हर साल जो बाढ़ आती है उस पर काबू पाया जा सके । अगर सरकार ने दीर्घकालीन योजना बनाई तो इससे बाढ़ रोकी जा सकती है । सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है और अधिक मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है जिससे देश को काफी फायदा होगा । मैं पुनः सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं उन इलाकों के लोगों के लिये सरकार समुचित सहायता की व्यवस्था करे और एक दीर्घकालीन योजना तैयार करे ताकि हमेशा के लिये बाढ़ की समस्या का समाधान हो सके । धन्यवाद ।